



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 1985/आश्विन 3, 1907

No. 459] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 1985/ASVINA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचनाएं

NOTIFICATIONS

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

New Delhi, the 25th September, 1985

का. आ. 692(अ).—जबकि जालंधर के न्यायिक
जोन में सम्मिलित क्षेत्र, आतंकवादी क्षेत्र नहीं रह गया है,

S.O. 692(E).—Whereas the area comprising the
judicial zone of Jalandhar has ceased to be a terrorist
affected area;

जबकि जालंधर के न्यायिक जोन से संबंधित विशेष
न्यायालय में कोई मामले पेडिंग नहीं हैं,

Whereas no cases are pending in the special court
in relation to the judicial zone of Jalandhar;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष
न्यायालय) अधिनियम, 1984 की धारा-15-क द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय
की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 542 (अ) दिनांक 28
जुलाई, 1984 के तहत यथास्थापित जालंधर न्यायिक जोन
से संबंधित विशेष न्यायालय को 28 सितम्बर, 1985 से
समाप्त करती है।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred
by section 15-A of the Terrorist Affected Areas
(Special Courts) Act, 1984, the Central Government
hereby abolishes with effect from the 28th September,
1985 the special court in relation to judicial zone of
Jalandhar as established under the Notification of
the Government of India in the Ministry of Home
Affairs No. GSR. 542 (E), dated the 28th July, 1984.

[स. 1/8/85-लीगल सेल]

[No. 1/8/85-Legal Cell]

का. आ. 693(अ).—जबकि पटियाला के न्यायिक ज़ोन में सम्मिलित क्षेत्र, आतंकवादी क्षेत्र नहीं रह गया है;

जबकि पटियाला के न्यायिक ज़ोन में संबंधित विशेष न्यायालय में कोई मामले पेंडिंग नहीं है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 543 (अ) दिनांक 28 जुलाई, 1984 के तहत यथास्थापित पटियाला न्यायिक ज़ोन में संबंधित विशेष न्यायालय को 28 सितम्बर, 1985 में समाप्त करती है।

[सं. 1/8/85-लीगल सेल]

S.O. 693(E).—Whereas the area comprising the judicial zone of Patiala has ceased to be a terrorist affected area;

Whereas no cases are pending in the special court in relation to the judicial zone of Patiala;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15-A of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, the Central Government hereby abolishes with effect from the 28th September, 1985, the special court in relation to judicial zone of Patiala as established under the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR. 543(E), dated the 28th July, 1984.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

का.आ. 694(अ).—जबकि फिरोज़पुर के न्यायिक ज़ोन में सम्मिलित क्षेत्र, आतंकवादी क्षेत्र नहीं रह गया है,

जबकि फिरोज़पुर के न्यायिक ज़ोन में संबंधित विशेष न्यायालय में कोई मामले पेंडिंग नहीं है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 28 जुलाई, 1984 के तहत यथास्थापित फिरोज़पुर न्यायिक ज़ोन में संबंधित विशेष न्यायालय को 28 सितम्बर, 1985 में समाप्त करती है।

[सं. 1/8/85-लीगल सेल]

S.O. 694(E).—Whereas the area comprising the judicial zone of Ferozepur has ceased to be a terrorist affected area;

Whereas no cases are pending in the special court in relation to the judicial zone of Ferozepur;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15-A of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, the Central Government hereby abolishes with effect from the 28th September, 1985, the Special court in relation to judicial zone of Ferozepur as established under the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR. 544(E) dated the 28th July, 1984.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

का. आ. 695(अ) —जबकि चंडीगढ़ के न्यायिक ज़ोन में सम्मिलित क्षेत्र, आतंकवादी क्षेत्र नहीं रह गया है;

जबकि चंडीगढ़ के न्यायिक ज़ोन में संबंधित विशेष न्यायालय में कोई मामले पेंडिंग नहीं है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 की धारा 15-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635(अ), दिनांक 31 अगस्त, 1984 के तहत यथास्थापित चंडीगढ़ न्यायिक ज़ोन में संबंधित विशेष न्यायालय को 28 सितम्बर, 1985 में समाप्त करती है।

[सं. 1/8/85-लीगल सेल]

ए के बसाक, सचिव, सचिव

S.O. 695 (E).—Whereas the area comprising the judicial zone of Chandigarh has ceased to be a terrorist affected area;

Whereas no cases are pending in the special court in relation to the judicial zone of Chandigarh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15-A of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, the Central Government hereby abolishes with effect from the 28th September, 1985, the special court in relation to judicial zone of Chandigarh as established under the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR. 635 (E), dated the 31st August, 1984.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

A. K. BASAK, Jt Secy.